भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या :1196

मंगलवार ,11 फरवरी 2025 ,को उत्तर दिए जाने के लिए

चेन्नई बेंगलुरु-औद्योगिक गलियारा

1196. डॉएम. के. विष्णु प्रसादः. .

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चेन्नईका ब्यौरा और स्थिति क्या है (सीबीआईसी) बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे-;

(ख) इस सीबीआईसी पर जारी और खर्च की गई कुल परियोजना लागत और निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सीबीआईसी के अंतर्गत आज की तारीख तक पूरी हो चुकी परियोजनाओं की स्थिति क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ग) : राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत, औद्योगिक कॉरिडोरों की परिकल्पना वैश्विक विनिर्माण को बढ़ावा देने, प्लग एंड प्ले सुविधा के साथ निवेश केंद्र, वॉक-टू-वर्क अवधारणा के साथ स्मार्ट शहरों और मांग पूर्व सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली अवसंरचना का निर्माण करने के लिए की गई है। सीबीआईसी उन 11 औद्योगिक कॉरिडोरों में से एक है, जिन्हें राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत बैंगलोर-चेन्नई एक्सप्रेसवे या राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे 7 (एनई-7) के साथ प्रमुख परिवहन माध्यम के रुप में विकसित किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा कर्नाटक के तुमकुरु और आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम में दो औद्योगिक टाउनशिप को अनुमोदन प्रदान किया गया है और इनका विकास किया जा रहा है। इनकी अद्यतन स्थिति निम्नलिखित है:

1. **कर्नाटक में तुमकुरु नोड:**

(क) भारत सरकार ने कर्नाटक में तुमकुरु नोड के चरण 1 में 1,736 एकड़ के एक्टिवेशन एरिया को अनुमोदन प्रदान किया है।

(ख) 1,701 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत में से, 586.74 करोड़ रुपए एनआईसीडीआईटी द्वारा जारी कर दिए गए हैं।

(ग) माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इस परियोजना की आधारशिला 06 फरवरी, 2023 को रखी गई।

(घ) इस परियोजना के विकास के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) का निगमन किया गया है। मुख्य अवसंरचना और संबंधित कार्यों के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) और ईपीसी ठेकेदार को नियुक्त कर लिया गया है।

2. आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम नोड:

(क) भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश के कृष्णापटनम नोड में 2,500 एकड़ के एक्टिवेशन एरिया को अनुमोदन प्रदान किया है।

(ख) 2,139 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत में से, 533.86 करोड़ रुपए एनआईसीडीआईटी द्वारा जारी कर दिए गए हैं।

(ग) माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इस परियोजना की आधारशिला 09 जनवरी, 2025 को रखी गई।

(घ) इस परियोजना के विकास के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) का निगमन किया गया है। मुख्य अवसंरचना और संबंधित कार्यों के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) और ईपीसी ठेकेदार को नियुक्त कर लिया गया है।

*****